जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत वितरण निगमों की वीडियों कॉन्फ्रेंस आयोजित
छीजत कम करने के कार्यों का रोडमैप निर्धारित

जयपुर, 24 अगस्त। विद्युत वितरण निगमों में हानि कम करने की योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण फीडरों पर अब तक हुए कार्य की प्रगति की वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से समीक्षा की गई। इसके तहत 30 सितम्बर तक सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाए जिससे की प्रथम चरण में चयनित फीडरों पर सुधार कार्य दिसम्बर 2016 तक पूरा हो सके।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छीजत कम करने और घाटे पर अंकुश लगाने की है। इसके लिए हानि कम करने की व्यापक योजना भी बन गयी है जिसमें डिस्कॉम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है इसके लिए इस प्रोगाम की जानकारी देने के लिए कई वर्कशॉप भी की जा चुकी है जिसमे योजना के अनुसार क्या कार्य करना है और कैसे करना है उसके बारे में बता दिया गया है। यह कार्य तभी संभव होगा जब हम सभी मिलकर और कार्य करेंगे। और राजस्थान को विद्युत क्षेत्र में पहले पायदान पर ले जाएगे।

विद्युत वितरण निगमों की बुधवार को आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंस में डिस्कॉम अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने 2 प्रतिशत से अधिक हानि वाले औद्योगिक क्षेत्रों में वास्तविक हानि का सत्यापन आगामी सात दिन में करने के लिए संभागीय मुख्य अभियन्ताओं को निर्देश दिये तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुसार हानि कम करने की पूर्ण जिम्मेदारी अधिशाषी अभियन्ताओं की रहेगी। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में जहां छीजत का स्तर 15 प्रतिशत से अधिक है उन क्षेत्रों में किये जाने वाले तकनीकी कार्य एवं विद्युत चोरी रोकने के लिए की जाने वाले कार्यवाही की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 सितम्बर तक तैयार कर ली जावे तथा शहरी क्षेत्र की स्थिति के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से समय पर सभी कार्य पूरे किये जाए।

प्रथम चरण में चिन्हित किये ग्रामीण फीडरों पर सर्वे का कार्य 10 सितम्बर तक पूरा कर लिया जावे और 25 सितम्बर तक इनके कार्य आदेश जारी कर सुधार के लिए आवश्यक सामान 30 सितम्बर तक उपलब्ध करावा दिया जाए। फीडर के अनुसार गठित की गई फीडर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक 10 सितम्बर को आयोजित की जावे और उस बैठक में निगम के उच्च अधिकारी भी भाग ले। यह केवल मैन्टेनेन्स का कार्य है और इसमे किसी भी प्रकार का पूंजीगत खर्चा नही होगा।

वीडियों कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जन सेवा केंद्रों पर उपस्थित फीडर इंचार्ज से भी हानि कम करने की योजना के बारे में डिस्कॉम चैयरमैन ने फीडबैक प्राप्त किया और कहा कि जो फीडबैक मिल रहा है कि उससे लगता है कि फीडर इंचार्ज योजना के तहत कार्यों से अवगत है।

ऊर्जा विभाग के सलाहकार आर जी गुप्ता ने तीनों डिस्कॉम में प्रथम चरण के लिए चयनित ग्रामीण फीडरों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सुझाव दिया कि फीडर इंचार्ज द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपार्ट पर फीडर इंचार्ज के हस्ताक्षर व मोबाईल नम्बर के साथ ही उस पर संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता के भी हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह कार्य 10 सितम्बर तक पूरी करके सूची को कम्प्यूटर पर डाल दी जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सामान की आवश्यकता का निर्धारण करके कार्य शुरू कर दिया जाए।

वीडियों कॉन्फ्रेंस में तीनों डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने अपने डिस्कॉम में हानि कम करने के लिए किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी।

.....

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 429/2016